

प्रेषक,  
अंजली प्रसाद,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
आई0सी0डी0एस0,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला-सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 17 अप्रैल, 2008

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेतर पक्ष की वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 270 (1)/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेतर पक्ष की प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार रुपये 48,50,000.00 (रुपये अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा आयोजनेतर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि हेतु व्यय/भुगतान हेतु परिधिगत अधिकारी से प्राप्त देयकों को विभाग में नियुक्त वित्त नियंत्रक अधिकारी के माध्यम/प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए एवं आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 270 (1)/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
8. बचनबद्ध मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उक्त बजट आवंटन के सापेक्ष यदि विगत वर्ष के कोई देयक अवशेष हो तो बिना शासन की अनुमति के उनका भुगतान कदापि न किया जाए तथा प्रत्येक वित्त नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से/प्रतिहस्ताक्षरित करा कर ही भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसका कड़ाई से पालन किया जाए।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।
13. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
16. उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या 6 (NP) /वि0अनु0-03/2008, दिनांक 10.04.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,  
अंजली प्रसाद  
(अंजली-प्रसाद)  
सचिव।

पृष्ठांक संख्या: 417(1)/XVII(2)/2008 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

अंजली प्रसाद  
(अंजली-प्रसाद)  
सचिव।